कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001
email id- election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1285 /XXV–12/2018 Part-10 देहरादूनः दिनांक 17 अगस्त, 2021.

सेवा में,

श्री बी0एस0शाही
ग्राम पदमपुर पडलिया
पो0ऑ0–लामाचौड़, तहसील हल्द्वानी
जिला नैनीताल।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 234/सू0काअ0/3013/2021 दिनांक 27 अगस्त 2021 के साथ आपका का अनुरोध पत्र दिनांक 10.08.2021 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, उक्त में मांगी गयी वांछित सूचना का विवरण निम्नवत संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्याः–1	विधान सभा 2017, आदर्श आचार संहिता पृष्ठ संख्या– 1से 07 तक विधान सभा 2017, अधिसूचना पृष्ठ संख्या –01 (कुल आठ)

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पताः–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़
देहरादून– 248001

भवदीय,

B-S.Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

4

प्राप्त - 10/8/21 95

पत्र वाहक / पंजीकृत

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 234 / सू0का0अ0 / 3013 / 2021 दिनांक 02 अगस्त, 2021

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री बी0एस0 शाही, ग्राम पदमपुर पड़लिया, पो0ऑ0–लामाचौड़, तहसील हल्द्वानी, जिला– नैनीताल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक अनुरोध–पत्र दिनांक 28.07.2021 राज्य निर्वाचन आयोग में प्रेषित किया गया है, जो आयोग में दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार रू0 10.00 का पोस्टल आर्डर भी आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

चूंकि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7534820731

संख्या–234 / सू0का0अ0 / 3013 / 2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री बी0एस0 शाही, ग्राम पदमपुर पड़लिया, पो0ऑ0–लामाचौड़, तहसील हल्द्वानी, जिला– नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

पंजीकृत
F-3013
R.no-945

सेवा मे, श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त महोदय,
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड।
निर्वाचन भवन देहरादून।

दिनांक:- 28/07/2021

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी बिन्दु पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
अवगत होना चाहे कि, अनुरोधकर्ता के द्वारा पूर्व मे अपने अनुरोध पत्र दिनांक- 12.05.2021 मे चाही गई बिन्दु सं०-(1) की सूचना आपके कार्या० पत्रांक सं०- 100/रा०नि०आ०-1/2013/2021 दिनांक- 22 जुलाई 2021 के द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदो, विकास खण्डों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पं० त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 19- आदर्श आचरण संहिता लागू की गई आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध हुई है। वर्तमान मे राज्य के 70 विधान सभा चुनाव हेतु पूर्व 2017 मे विधान सभा निर्वाचन हेतु सामान्य निर्वाचन - 2017 जारी अधिसूचना/आदेश की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या - (01) उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व माह जनवरी 2017 मे विधान सभा-70 क्षेत्रो मे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पुनः चुनाव सम्पन्न कराये गये है। उक्त के क्रम राज्य के (70) विधान सभा क्षेत्र हेतु माह दिसम्बर या जनवरी 2017 मे राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा सामान्य निर्वाचन 2017 आदर्श आचरण संहिता' लागू की गई, अधिसूचना-आदेश निर्गत किया गया, सूचना की प्रतिलिपि प्रमाणित कर उपलब्ध कराये।

संलग्नक- 01 भारतीय पोस्टल आर्डर सं०-
(54 F 575834)।

भवदीय
अनुरोधकर्ता
हस्ताक्षर
बी० एस० [illegible]
ग्राम - पदमपुर [illegible]
पो० ओ० [illegible]
जिला - नैनीताल
उत्तराखण्ड।

श्री दिनेश
कृ० PIO, CEO को हस्तांतरण
हेतु पत्रावली प्रस्तुत करें।
02.08.2021
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

Received No [illegible] 10/2
[illegible]/8/21

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– 42 /XXV – 39/ 2016 देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2017

ELECTION-URGENT

सेवा में,

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5– समस्त सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6– समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषयः– विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2017– आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में आयोग के निदेशों का प्रेषण

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–437/6/1/ECI/INST/FUNCT /MCC/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, आयोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी, 2017 को विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श–आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। आयोग द्वारा अपने उक्त पत्र में मा. मंत्रिगणों के भ्रमण, शासकीय वाहनों, शासकीय मशीनरी, हैलीपैड, एयर–क्राफ्ट, रेस्ट हाऊस–डाक बंग्लॉ, विवेकाधीन कोष, शासकीय धन से प्रचार–प्रसार, किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान की घोषणा, सड़क–पेयजल आदि के लिए कोई वादा करना एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण आदि के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– उक्त के अतिरिक्त आयोग के पत्र संख्या–437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 जिसमें Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development scheme. के संदर्भ में भी विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं, की प्रति भी तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि आयोग के उक्त संदर्भित पत्रों में जारी आदर्श आचार संहिता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या– 42 /XXV – 39 / 2016, तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को भारत निर्वाचन आयोग के उक्त संदर्भित पत्रों की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री/मा. समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
3– प्रदेश अध्यक्ष/मंत्री/सचिव, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल उत्तराखण्ड।
4– सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

By Fax/Spl. Messenger/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017 **Dated: 4th January, 2017**

To

1. The Cabinet Secretary,
   Government of India,
   Rashtrapati Bhawan,
   New Delhi.

2. The Secretary to the Government of India,
   Department of Programme Implementation,
   Sardar Patel Bhawan,
   New Delhi.

3. The Chief Secretaries to the Government of :-
   (i) Goa, Panaji;
   (ii) Manipur, Imphal;
   (iii) Punjab, Chandigarh;
   (iv) Uttarakhand, Dehradun;
   (v) Uttar Pradesh, Lucknow.

4. The Chief Electoral Officers of :-
   (i) Goa, Panaji;
   (ii) Manipur, Imphal;
   (iii) Punjab, Chandigarh;
   (iv) Uttarakhand, Dehradun;
   (v) Uttar Pradesh, Lucknow.

Subject: **General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017- Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme.**

Sir,

I am directed to refer to the Commission's Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 4th January, 2017 (Press Note available at Commission's web-site – **www.eci.gov.in**) as per which the Commission has announced the enforcement of the Model Code of Conduct for the guidance of the Political Parties and Candidates,

consequent on the announcement of General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017.

2. The Commission has instructed that the release of funds under the Member of Parliament Local Area Development Schemes will be subject to the following restrictions:-

a) No fresh release of funds under the Member of Parliament (including Rajya Sabha members) Local Area Development fund shall be made in any part of the country where election is in progress. Similarly no fresh release of funds under the MLAs'/ MLCs' Local Area Development Fund shall be made, if any such scheme is in operation, till the completion of election process.

b) No work shall start in respect of which work orders have been issued before the issue of this letter <u>but</u> the work has actually not started in the field. These works can start only after the completion of election process. However, if a work has actually started, that can continue.

c) There shall be no bar to the release of payments for completed work(s) subject to the full satisfaction of the concerned officials.

d) Where schemes have been cleared and funds are provided or released and materials procured and reached the site such scheme may be executed as per programme.

Yours faithfully,

(R.K. SRIVASTAVA)
SR. PRINCIPAL SECRETARY

(4)

By Spl. Messenger/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017 **Dated: 4th January, 2017**

To

1. The Cabinet Secretary,
   Government of India,
   Rashtrapati Bhawan,
   New Delhi.

2. The Chief Secretaries to the Government of :-
   (i) Goa, Panaji;
   (ii) Manipur, Imphal;
   (iii) Punjab, Chandigarh;
   (iv) Uttarakhand, Dehradun;
   (v) Uttar Pradesh, Lucknow.

3. The Chief Electoral Officers of :-
   (i) Goa, Panaji;
   (ii) Manipur, Imphal;
   (iii) Punjab, Chandigarh;
   (iv) Uttarakhand, Dehradun;
   (v) Uttar Pradesh, Lucknow.

Sub: Application of Model Code of Conduct – General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017– reg.

Sir,

I am directed to state that the Commission has announced the schedule for holding General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017 (Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 4th January, 2017 available at Commission's web-site – **www.eci.gov.in**).

2. With this announcement, the provisions of the Model Code of Conduct for the guidance of the Political Parties and Candidates have come into force with immediate effect and will be in force till the completion of the General Elections. This may be brought to the notice of the Central/State Government, all Ministries/Departments and all other offices of the Union Government and the State Government of the States. A copy of instructions issued by you may be sent to Election Commission of India for information and record.

3. Your particular attention is drawn to the provisions of Model Code of Conduct for the guidance of Political Parties and Candidates and various instructions issued by the Commission, which, inter-alia, state that the party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular: -

(i) (a) The Ministers shall not combine their official visit with electioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work;

(b) Government transport including official air-crafts, vehicles, machinery and personnel shall not be used for furtherance of the interest of the party in power;

(ii) Public places such as maidans etc., for holding election meetings, and use of helipads for air-flights in connection with elections shall not be monopolised by itself. Other parties and candidates shall be allowed the use of such places and facilities on the same terms and conditions on which they are used by the party in power;

(iii) Rest houses, dak bungalows or other Government accommodation where elections have been announced or are taking place can be given to the political functionaries who are provided security by the State in Z scale or above or equivalent by various State Governments or the Central Government under provisions of their laws, on equitable basis. This shall be subject to condition that such accommodation is not already allotted or occupied by election related officials or Observers. Such political functionaries shall not carry out any political activity while staying in the Government Guest Houses/Rest Houses or other Government accommodation etc.;

(iv) Issue of advertisement at the cost of public exchequer in the newspapers and other media and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided;

(v) Ministers and other authorities shall not sanction grants/payments out of discretionary funds from the time elections are announced by the Commission; and

(vi) From the time elections are announced by Commission, Ministers and other authorities shall not –

(a) announce any financial grants in any form or promises thereof; or

(b) (except civil servants) lay foundation stones etc. of projects or schemes of any kind; or

(c) make any promise of construction of roads, provision of drinking water facilities etc.; or

(d) make any ad-hoc appointments in Government, Public Undertakings etc. which may have the effect of influencing the voters in favour of the party in power.

4. As will be observed from Para 3{Clause IV} above, no advertisements shall be issued in electronic and print media highlighting the achievements of the Govt. at the cost of public exchequer. If any advertisement has already been released for telecast/broadcast or publication in the print media, it must be ensured that the telecast/broadcast of such ads on electronic media is stopped forthwith and that no such ad is published in any newspapers, magazines, etc., i.e. in print media, from today itself and it should be immediately withdrawn.

5. The instruction of the Commission contained in its letter No.437/6/2009-CCBE dated 5th March, 2009 is available on the Commission's web-site "http://eci.nic.in/ under the heading 'Election Laws and ECI - instructions' for your information and necessary action. The Commission's all other instructions are also available in this link for your guidance.

6. The Commission directs that there shall be a total ban on the transfer of all officers/officials connected with the conduct of the election. These include but are not restricted to: -

i) The Chief Electoral Officer and Additional/Joint/Deputy Chief Electoral Officers;

ii) Divisional Commissioners;

iii) The District Election Officers, Returning Officers, Assistant Returning Officers and other Revenue Officers connected with the Conduct of Election;

iv) Officers of the Police Department connected with the management of election like range IGs and DIGs, Senior Superintendents of Police and Superintendents of Police, Sub-Divisional Police Officers like Deputy Superintendents of Police and other Police officers who are deputed to the Commission under section 28A of the Representation of the People Act, 1951;

v) The transfer orders issued in respect of the above categories of officers prior to the date of announcement but not implemented till date should not be given effect to without obtaining specific permission from the Commission in this regard;

vi) This ban shall be effective till the completion of the election. The Commission further directs that the State Governments should refrain from making transfers of senior officers who have a role in the management of election in the State;

vii) In those cases where transfer of an officer is necessary on account of administrative exigencies, the concerned State Government may with full justification approach the Commission for prior clearance.

7. The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(R.K. SRIVASTAVA)
SR. PRINCIPAL SECRETARY

1-8

उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में तारीख 20 जनवरी 2017 (शुक्रवार) को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 20 जनवरी, 2017
30 पौष 1938 (शक)

अधिसूचना

सं0 464/भा0नि0आ0/क्षे0/उ0अनु0-2/उत्तरा0-वि0स0/2017:- यतः उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी तथा 20 जनवरी, 2017 (शुक्रवार) को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम तथा तद्वीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधो के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः-

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता हैः-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	27 जनवरी, 2017 (शुक्रवार);
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	30 जनवरी, 2017 (सोमवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	01 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	15 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(ड)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा।	15 मार्च, 2017 (बुधवार); और

(आ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

(राहुल शर्मा)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग